दिनांक: 16 सितम्बर 2023

डीजल वाहनों पर प्रस्तावित अतिरिक्त कर

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "डीजल वाहनों पर प्रस्तावित अतिरिक्त कर" शामिल है। यह विषय यह संघ लोक सेवा के सिविल सेवा परीक्षा के "भारतीय अर्थव्यवस्था" खंड में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *डीजल वाहन*
- *डीजल वाहनों के फायदे क्या हैं?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन-03: भारतीय अर्थव्यवस्था*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल ईंधन का उपयोग कम करने पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि डीजल वाहनों और जनरेटर का उपयोग जारी रहता है, तो वह वित्त मंत्री को "प्रदूषण कर" के रूप में 10% जीएसटी वृद्धि का सुझाव दे सकते हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं है।

भारतीयों में डीजल का विरोध-

- **सरकार के हरित उद्देश्य:** भारत सरकार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना चाहती है और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए 2070 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी 40% बिजली का उत्पादन करना चाहती है।
- **कर का बोझ:** सरकार वर्तमान में डीजल वाहनों पर इंजन आकार के आधार पर अतिरिक्त उपकर के साथ 28 प्रतिशत कर लगाती है।
- **उत्सर्जन दुविधा:** डीजल इंजनों द्वारा उत्पादित नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), का उच्च स्तर पर्यावरण के बारे में चिंता पैदा करता है। 2015 में वोक्सवैगन घोटाले से डीजल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और नुकसान हुआ।
- **ईंधन दक्षता:** हालांकि डीजल इंजन बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और टोक़ प्रदान करते हैं, डीजल और पेट्रोल के बीच मूल्य अंतर 2014 में ईंधन मूल्य विनियमन के बाद से कम हो गया है।
- **महंगे अपग्रेड:** 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव और इन मानकों का पालन करने के लिए डीजल इंजनों के लिए आवश्यक महंगे अपग्रेड ने कार निर्माताओं को डीजल बाजार से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। उनका तर्क था कि बीएस-4 से बीएस-6 में जाने से डीजल मॉडल आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाते हैं।

भारत में डीजल वाहनों की स्थिति:-

- **डीजल की हिस्सेदारी:** पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल का अनुमान है कि भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीजल की हिस्सेदारी लगभग 40% है।
- **परिवहन प्रभुत्व:** कुल डीजल बिक्री का लगभग 87% परिवहन क्षेत्र की सेवा करता है, जिसमें ट्रक और बसों भारत में डीजल की बिक्री का लगभग 68% हिस्सा बनाती हैं।

- तीन राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, सामूहिक रूप से देश में डीजल की बिक्री का लगभग 40% हिस्सा हैं।

डीजल कारों पर असर-

- भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल, 2020 को डीजल वाहनों का उत्पादन बंद कर दिया, और इस बाजार में फिर से प्रवेश करने की योजना नहीं है।
- टाटा मोटर्स, महिंद्रा और होंडा अब 1.2-लीटर डीजल इंजन का उत्पादन नहीं करती हैं; वे अब केवल 1.5-लीटर या बड़े इंजन के लिए डीजल विकल्प प्रदान करते हैं।
- हालाँकि हुंडई, किआ और टोयोटा अभी भी कुछ डीजल मॉडल पेश करते हैं, अधिकांश वाहन निर्माताओं ने 2020 के बाद से अपनी डीजल उत्पाद श्रृंखला में भारी कमी कर दी है।
- परिणामस्वरूप, डीजल की कुल मांग में यात्री वाहनों की हिस्सेदारी 2013 में 28.5% से घटकर 2018 में 16.5% हो गई है।

डीजल वाहनों के लाभ-

- **अधिक दक्षता:** कुछ व्यक्तिगत उपयोगकर्ता बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के कारण डीजल पसंद करते हैं। डीजल ईंधन में प्रति लीटर अधिक ऊर्जा होती है, और डीजल इंजन, जो उच्च संपीड़न अनुपात और बिना स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं, स्वाभाविक रूप से कुशल होते हैं।
- **अधिक ऊर्जा:** भारी वाहनों और ढुलाई के लिए डीजल इंजन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे अधिक टॉर्क प्रदान करते हैं और उनके रुकने की संभावना कम होती है।
- **सस्ता ईंधन:** ऐतिहासिक रूप से, पेट्रोल की तुलना में कम डीजल की कीमतें व्यक्तिगत कार मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण थीं, जिसमें अपने चरम पर पर्याप्त मूल्य अंतर होता हैं।

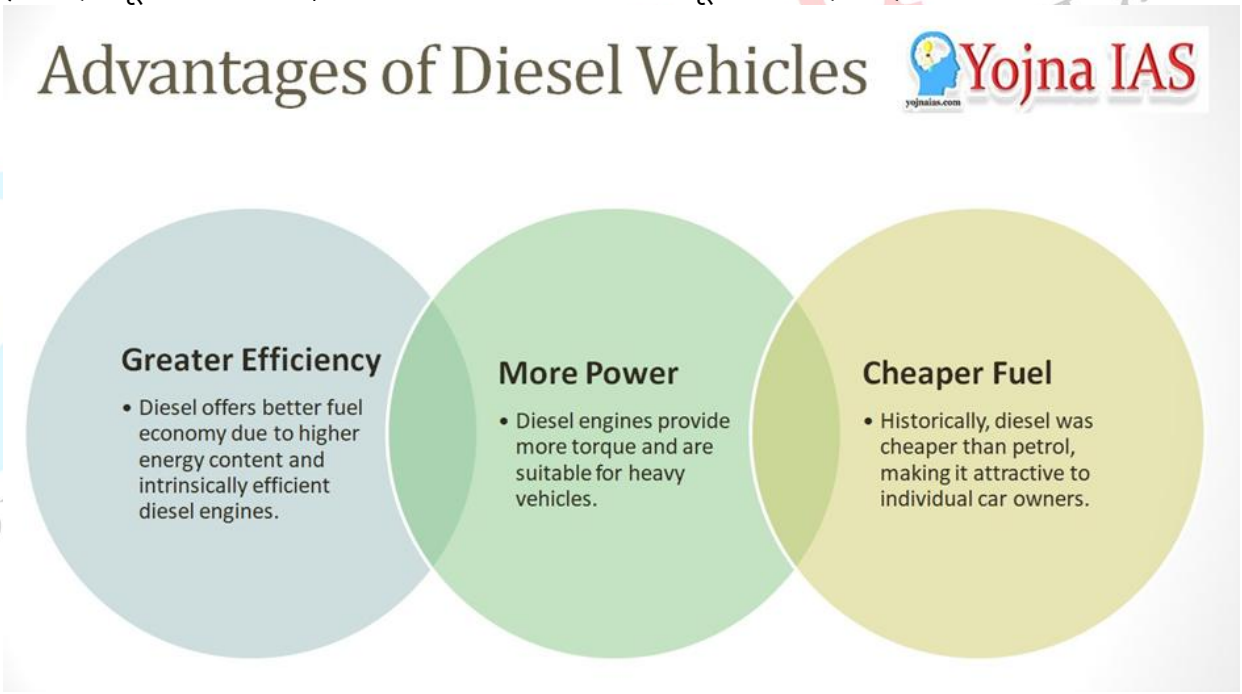

आगे का रास्ता:

- **इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना** : ईवी डीजल वाहनों के लिए एक स्वच्छ और कुशल विकल्प हैं। सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है, जैसे कि सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और तरजीही पार्किंग।
- **सार्वजनिक परिवहन में सुधार: सार्वजनिक परिवहन** निजी वाहनों की तुलना में यात्रा करने का एक अधिक टिकाऊ तरीका है। सरकार बसों, ट्रेनों और मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्पों के विस्तार और सुधार में निवेश कर सकती है।

- **शहरों में भीड़ मूल्य निर्धारण लागू करें: भीड़ मूल्य निर्धारण** ड्राइवरों को पीक ट्रैफ़िक समय के दौरान कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए शुल्क लेता है। यह यातायात की भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है और लोगों को सार्वजनिक परिवहन या अन्य विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

स्त्रोत-केंद्र ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में वाहन निर्माताओं को उच्च करों की चेतावनी दी

प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा

प्रश्न 1. डीजल वाहनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. डीजल में प्रति लीटर उच्च ऊर्जा सामग्री होती है, जो इसे आंतरिक रूप से कुशल बनाती है।
2. डीजल इंजन अधिक टोक़ प्रदान करते हैं, जिससे वे भारी भार को खींचने के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं।
3. भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में डीजल की हिस्सेदारी लगभग 70% है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) उपरोक्त में कोई नहीं

उत्तर: (a)

प्रश्न-2. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. बायोडीजल और इथेनॉल जैसे ईंधन के उपयोग पर कर लगाना।
2. शहरों में भीड़ मूल्य निर्धारण को लागू करना।
3. सीएनजी और एलपीजी को प्रोत्साहित करना।
4. कड़े उत्सर्जन मानकों को लागू करना।

उपरोक्त उपायों में से कितने भारत में डीजल की खपत को कम करने में मदद कर सकते हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) केवल तीन
(d) उपरोक्त में सभी।

उत्तर: (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3. भारत में डीजल के वाहनों को कम करने की मांग देखी जा रही है और देश में डीजल की खपत को कम कैसे किया जाए चर्चा कीजिए।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

Rajiv Pandey

रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा" शा मिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसआर) के बारे में?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्यय-03: विज्ञान और प्रौद्योगिकी*

- *भारत के रोबोटिक्स क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां?*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में,"रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति" का मसौदा जारी किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने जनता और अन्य हितधारकों को टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया है। ".

लक्ष्य:

- रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन (एनआरएम), का लक्ष्य इन पहलों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे के निर्माण के साथ-साथ रोबोटिक्स नवाचार चक्र के सभी पहलुओं को मजबूत करना है।

उद्देश्यों:

- 2030 तक रोबोटिक्स में भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उन्नत एकीकरण के लिए मेक इन इंडिया0 पहल को मजबूत करना

नोडल एजेंसी:

- राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन (एनआरएम), जिसका नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) कर रहा है, इस प्रयास का नेतृत्व करेगा

कोर सेक्टर: प्रमुख क्षेत्रों में रोबोटिक्स स्वचालन को प्राथमिकता देना-

- निर्माण
- कृषि
- स्वास्थ्य देखभाल
- राष्ट्रीय सुरक्षा

उपाय: रोबोटिक्स नवाचार को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है:

- द्वारा राजकोषीय और गैर-राजकोषीय हस्तक्षेप।
- रोबोटिक्स स्टार्ट-अप के लिए वित्त पोषण तंत्र का विकास।
- रोबोटिक निर्यात को बढ़ावा।

महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें:-

- **मजबूत नियामक ढांचा:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को अपने निर्देशन में एक स्थिर नियामक ढाँचा स्थापित करना चाहिए।
- **रोबोटिक्स उत्कृष्टता केंद्र (CoEs):** मौलिक और अनुप्रयुक्त रोबोटिक्स अनुसंधान के लिए सीओई स्थापित करें। प्रारंभिक व्यावसायीकरण और प्रायोगिक प्रोटोटाइप के लिए प्राथमिकता वाले उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **स्टार्टअप के लिए समर्थन: स्टार्टअप** को सहायता प्रदान करना, उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान क्षमता का दोहन करना और समर्पित रोबोटिक्स औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना।
- **सार्वजनिक खरीद नीति:** रोबोटिक्स के लिए एक सार्वजनिक खरीद नीति लागू करें, जिससे केंद्र सरकार भारतीय निर्मित रोबोटिक प्रणालियों की एक महत्वपूर्ण खरीदार बन जाए, और न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकता के साथ घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करे।

भारत के रोबोटिक्स क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां:-

- **आयात पर निर्भरता:** भारत मुख्य रूप से चीन और जापान से रोबोटिक्स घटकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जो आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आत्मनिर्भरता पर सवाल उठाता है।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- **महंगा हार्डवेयर:** रोबोटिक्स हार्डवेयर घटकों से जुड़ी उच्च लागत रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा करती है, खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के लिए।
- **सीमित अनुसंधान और विकास: अनुसंधान** और विकास (आर एंड डी) में अपर्याप्त निवेश रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी में प्रगति में बाधा डालते हैं। एक मजबूत आर एंड डी पारिस्थितिकी तंत्र की कमी उन्नत रोबोटिक्स समाधानों के नवाचार और स्वदेशी विकास में बाधा डालती है।

स्रोत: https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Draft-National-Strategy-Robotics।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसआर) के मसौदे के संदर्भ में , निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य 2030 तक रोबोटिक्स में भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 'राष्ट्रीय रोबोटिक्स मिशन' (NRM) के माध्यम से प्रयास का नेतृत्व करेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा प्रश्न –

प्रश्न-02 भारत में रोबोटिक्स के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसआर) के मसौदे में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों और सिफारिशों पर नवाचार को बढ़ावा देने में इस रणनीति के महत्व का विश्लेषण करें।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com